प्रस्तावना

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (एनकेसी) राष्ट्र के प्रति अपनी दूसरा वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते समय राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा 11वीं योजना में अपनाई गई ज्ञान पहलों के प्रति यूपीए सरकार की प्रतिबद्धता को लेकर उत्साहित है। योजना, विस्तार, उत्कृष्टता और समानता पर विशेष बल देते हुए त्वरित और समावेशी उन्नति प्राप्त करने के लिए एक केन्द्रीय उपकरण के रूप में शिक्षा को उच्च प्राथमिकता प्रदान करती है। यह बात तीन ट्रिलियन रुपए के प्रस्तावित आबंटन से प्रकट होती है जो कि 10वीं योजना की तुलना में पांच गुना वृद्धि का परिचायक है। इस प्रकार समग्र योजना में शिक्षा का हिस्सा 7.7 प्रतिशत से बढ़कर 20: हो जाएगा जो कि जीडीपी के छः प्रतिशत के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति कही जा सकती है। हमारे प्रधानमंत्री की कल्पना और राजनैतिक दायरे से हटकर से हमारे नेतृत्व को मिल रहा समर्थन निश्चय ही प्रशंसनीय है। सरकारी नियोजन के इतिहास में यह एक ऐतिहासिक पहल है। हमारा मानना है कि 11वीं योजना में निहित शिक्षा की कार्यसूची एक–समान समाज का लक्ष्य पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही यह हमारी सतत उन्नति, रोजगार सृजन, आधारिक सुविधाओं के निर्माण तथा अन्य विकासात्मक प्राथमिकताओं के लिए एक बुनियादी तत्व है।

राष्ट्र को प्रस्तुत दूसरी रिपोर्ट में पोर्टलों, स्वास्थ्य सूचना नेटवर्क, विधिक शिक्षा, चिकित्सीय शिक्षा, प्रबंध शिक्षा, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा, मुक्त शैक्षिक संसाधनों, नवाचार, बौद्धिक संपदा अधिकारों, सरकारी वित्तपोषित अनुसंधान के लिए कानूनी तंत्र तथा परंपरागत स्वास्थ्य प्रणालियों पर सिफारिशें शामिल हैं। पिछली दो रिपोर्टों को मिलाकर आयोग ने अब तक 20 विषय शामिल किए हैं और लगभग 160 ठोस कार्य मदें प्रस्तुत की हैं। साथ ही आयोग ने शिक्षा पर अपनी सिफारिशों का एक संचयन नवंबर, 2007 में प्रकाशित किया है जो कि समय 11वीं योजना के दस्तावेज संबंधी अंतिम चर्चाओं के समय से मेल खाता है। शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, पुस्तकालयों, अनुवाद, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क, नवाचार, आईपीआर, परंपरागत स्वास्थ्य प्रणालियों आदि से संबंधित हमारी अधिकांश सिफारिशें योजना में समाहित हैं और समुचित रूप से वित्तपोषित हैं।

हमारी सिफारिशें वेब के माध्यम से भी सुलभ हैं और उन्हें व्यापक रूप से वितरित किया गया है, चर्चा की गई है, बहस की गई है और उनके कार्यान्वयन के बारे में सरकार में विभिन्न स्तरों पर विचार किया जा रहा है। आयोग को विद्वानों, वैज्ञानिकों, अध्यापकों तथा सरकारी और निजी–दोनों क्षेत्रों के विभिन्न अन्य हितधारकों से उत्कृष्ट जानकारी और सलाह प्राप्त हुई है। प्रधानमंत्री कार्यालय और मंत्रिमंडल सचिवालय ने हमारी सिफारिशों को आगे बढ़ाने में उल्लेखनीय सहयोग प्रदान किया है। वास्तव में उनके सहयोग और प्रोत्साहन के लिए हम उन सबके आभारी हैं।

राष्ट्र को समर्पित 12 जनवरी, 2007 को एनकेसी की पहली रिपोर्ट का विमोचन करते समय प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया था कि आयोग को 'अपने नवाचारी विचारों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने में अवश्य सहयोजित किया जाना चाहिए'। अतः हमारा ध्यान यह सुनिश्चित करने में रहा है कि जहां केन्द्र सरकार हमारी सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए वित्तीय आबंटनों से समर्थित समुचित कार्यनीतियां तैयार करेगी, और इसके साथ–साथ हम अनुकूल राय का एक जनमत तैयार करने तथा जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन कार्यनीतियां तैयार करने में सहायता प्रदान करने के लिए विविध हितधारकों के साथ काम करेंगे। सिफारिशें तैयार करने और इसके बाद उनके प्रसार–दोनों कामों में हितधारकों के एक व्यापक और वैविध्यपूर्ण समूह के साथ बराबर बातचीत करते रहना हमारी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। हमने विचारों के आदान–प्रदान और उन पर चर्चा करने का, जो कि बदलाव को स्वीकार करने और उसे गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण पूर्वापेक्षा होती है, एक मंच प्रस्तुत उपलब्ध कराने का प्रयास किया है।

अब हम अपने कार्य के अगले चरण अर्थात राज्य और जिला स्तरों पर ज्ञान पहलें तैयार करने की ओर बढ़ रहे हैं जिससे कि 11वीं योजना के वित्तीय परिव्यय को खपाने के लिए जमीनी स्तर पर संस्थानगत और मानसिक रुप से तत्परता सुनिश्चित की जा सके। इस लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में संप्रति हम लगभग 17 राज्यों के साथ चर्चा में व्यस्त हैं।

पिछले एक वर्ष में विभिन्न सरकारी मंत्रालयों और एजेंसियों के साथ कार्यान्यवन संबंधी अपने कार्य के आधार पर हमने निम्न शिक्षाएं अर्जित की हैं:

- व्यक्तिगत उन्नति और विकास की पूर्ति के एक साधन के रूप में शिक्षा को लेकर निश्चय ही बहुत उत्साह और बल दिया जा रहा है। समाज के विभिन्न अंगों के बीच बच्चों और माता–पिता की बढ़ती हुई आकांक्षाएं, शिक्षा के लिए बढ़ती हुई मांग में जो कि आपूर्ति की तुलना में बहुत अधिक हो गई है परिलक्षित होती हैं।
- सरकार में विभिन्न स्तरों पर क्षेत्रीय सोच सहित कठोर संगठनात्मक तंत्रों के कारण नए विचारों, प्रयोगों, पुनर्निर्माण प्रक्रिया बाह्य हस्तक्षेपों, पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर अभी भी विरोध बना हुआ है।
- फलतः असली चुनौती हमारे विनियामक तंत्रों, नई आपूर्ति प्रणालियों, नई प्रक्रियाओं आदि में संगठनात्मक नवाचार लाने से जुड़ी हुई है। उनके अभाव में संसाधन बढ़ाने का परिणाम उसी तरह की स्थिति के रूप में हो सकता है।
- सभी समाधानों के लिए 'एक आकार फिट है' की दृष्टि से हमारा देश बहुत विशाल, अत्यधिक जटिल और वैविध्यपूर्ण है। कार्यान्वयन के लिए प्रभावी कार्यक्रम तैयार करने के लिए स्थानीय स्तर पर विकेन्द्रीकरण तथा सामुदायिक सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण होगी।
- हमें विभिन्न सहयोगात्मक माडल तैयार करने होंगे, परस्पर शंकाएं दूर करनी होंगी। अलग–अलग स्थानों में काम करने की बजाय सरकारी–निजी सहभागिता, विद्वत्समाज–उद्योग सहभागिता, विद्वत्समाज–अनुसंधान प्रयोगशालाओं, सरकारी–एनजीओ, सरकार–समुदाय आदि को माडल बनाए जाने की जरूरत है।
- यह काम समुचित नेतृत्व, स्वायत्तता, विनम्रता, जवाबदेही, दृश्य लक्ष्यों, मापनयोग्य माइल्स्टोनों और सुपरिभाषित विशिष्ट लक्ष्यों सहित बहुविध क्षेत्रों में शिक्षा पर केन्द्रित मिशन शुरू करने के जरिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है।
- नवाचार और उद्यमशीलता भारत की उन्नति की कथा को आगे ले जाने में प्रमुख प्रेरक रहे हैं और बने रहेंगे। कुशल जनशक्ति सहित वे ऐसे पिरामिड का निर्माण करते हैं जिसके ऊपर हमारा आर्थिक शक्ति–केन्द्र का निर्माण होगा। हमारी शिक्षा प्रणाली को सभी स्तरों अर्थात स्कूल, व्यावसायिक, उच्चतर और तकनीकी स्तरों पर चुनौती का सामना करना होगा।

जो पीढ़िगत बदलाव हमने सुझाए हैं, उन बदलावों को लाने के लिए हम केन्द्र और राज्य सरकारों सहित बहुविध हितधारकों के साथ काम करने की आशा करते हैं। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रभावी कार्यान्वयन जो कि ऊपर बताए गए कुछेक संगठनात्मक और संरचनात्मक बदलावों को ध्यान में रखता है, अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। इसके लिए सभी पक्षों से एक खुले दिमाग से एकजुट प्रयास करना और समुदाय की सक्रिय सहभागिता जरूरी होगी। आयोग को आशा है कि वह इस मिशन में एक प्रेरक के रूप में काम करेगा।

सैम पित्रोदा
अध्यक्ष,
राष्ट्रीय ज्ञान आयोग